सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक 277 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, मंगलवार 17 नवम्बर, 2026
मूल्य ₹ 3/-





समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और और जो आज करना है उसे अभी करो, कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जायेगा फिर तुम क्या कर पाओगे !! कबीर दास

जय शाह को दूसरी बार मिली आईसीसी... 7 | छठ पूजा पर सियासी बयान... 3 | जनसमर्थन के लिए कथा करा... 2

अब 9 दिसंबर को खुलेगा 48 सवालों का पिटारा, सुनवाई टली

ज्ञानेश कुमार और दो अन्य आयुक्तों के साथ आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत पूछताछ की मांगी है इंडिया गठबंधन ने इजाजत



» सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में होनी थी सुनवाई

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मुकदमें की तारीख लगी थी जिसके परिणाम से देश की सियासत में भूचाल आना तय था। एसआईआर पर इंडिया गठबधन के पूछे गये 48 सवालों पर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई होनी थी फिलहाल अभी यह टल गई है अब यह सुनवाई अगले महीने 9 दिसंबर को होगी।

बता दें राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन ने 48 सवालों की ऐसी फेहरिस्त अदालत के सामने रखी है जिसमें आयोग के फैसलों की तारीख, फाइल नंबर, मंजूरी का तरीका, आयुक्तों की सहमति–असहमति और डिजिटल मतदाता सूची में हुई हरकतों तक का हिसाब मांगा गया है। सवाल फैसला किसने लिया? सवाल यह भी है कि फाइल पर किसने दस्तखत किए, किसने सहमति दी, किसने आपत्ति जताई और क्या कोई फैसला ऐसा भी था, जिसकी जानकारी आयोग के अपने रिकॉर्ड में ही साफ-साफ दर्ज नहीं है? फार्म-6 में बदलाव किसके आदेश पर हुआ? मतदाता सूची से नाम हटाने और फिर उन्हें बहाल करने की व्यवस्था किसके नियंत्रण में रही? डिजिटल सिस्टम में बदलाव का पूरा लेखा–जोखा कहां है?

विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई टली

चुनाव आयोग के कामकाज और विभिन्न राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दायर राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 9 दिसंबर तय की है। विपक्ष की तरफ से दाखिल नई अर्जी पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने नोटिस जारी करने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान तय करेंगे। नई अर्जी के जरिए विपक्ष ने 48 सवाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों से पूछने की इजाजत मांगी है। 16 नवंबर को विपक्षी नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था। विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों निर्वाचन आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी। अपने हलफनामे में विपक्षी गठबंधन ने आयोग से पूछने के लिए वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े 48 बुनियादी सवाल पूछे थे। हलफनामे में आरोप लगाया था कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें वोट चोरी और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े किसी भी मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया गया है।

48

सवालों की ऐसी फेहरिस्त अदालत के सामने रखी है जिसमें आयोग के फैसलों की तारीख, फाइल नंबर, मंजूरी का तरीका, आयुक्तों की सहमति-असहमति और डिजिटल मतदाता सूची में हुई हरकतों तक का हिसाब मांगा गया है।

सवाल नम्बर दो- दो आयुक्तों ने कितनी बार असहमति जताई?





19

फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 तक की अवधि का पूरा ब्यौरा विपक्ष ने मांगा है।

इस विवाद का दूसरा सिरा आयोग के भीतर संभावित मतभेदों से जुड़ा है। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने एसआईआर, ईसीआईनेट, फॉर्म-6 और कुछ अन्य प्रशासनिक फैसलों पर कितनी बार लिखित आपत्ति या असहमति दर्ज कराई? विपक्ष ने 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 तक की अवधि का पूरा ब्यौरा मांगा है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में दोनों आयुक्तों की ओर से कम से कम 14 मौकों पर आपत्ति या चिंता दर्ज किए जाने का दावा किया गया था। इस रिपोर्ट के बाद आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर बहस तेज हुई। विपक्ष अब उसी बहस को अदालत के सामने दस्तावेजों के साथ परखना चाहता है। 48 सवालों में यह भी पूछा गया है कि क्या एसआईआर से जुड़े किसी फैसले में बहुमत का सहारा लिया गया था? यदि हां, तो किस फैसले में किस सदस्य ने असहमति जताई? क्या आपत्तियां अंतिम निर्णय में दर्ज हुईं या फाइल की टिप्पणियों तक सीमित रहीं?

सवाल नम्बर तीन- फॉर्म-6 में बदलाव किसके आदेश पर?

नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल होता है। एसआईआर के दौरान इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अतिरिक्त घोषणा जोड़े जाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ। विपक्ष ने पूछा है कि यह घोषणा जोड़ने का फैसला किसने लिया? किस अधिकारी ने इसे मंजूरी दी? क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति ली गई थी? क्या इसके कारण किसी आवेदन को लंबित रखा गया या अस्वीकार किया गया?

सवाल नम्बर चार- वोटर लिस्ट का डिजिटल दरवाजा किसके हाथ में?

48 सवालों का सबसे तकनीकी और संवेदनशील हिस्सा ईआरओनेट और ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। ये डिजिटल व्यवस्थाएं मतदाता सूची से संबंधित कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विपक्ष ने पूछा है कि इन प्लेटफॉर्म को केंद्रीकृत करने और मतदाता सूची तक पहुंच का नियंत्रण केंद्रीय स्तर पर रखने का फैसला किसने किया? किस अधिकारी को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, बदलने या बहाल करने का अधिकार था? क्या निजी कंपनियों, ठेकेदारों या बाहरी तकनीकी एजेंसियों के कर्मचारियों को भी डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति थी? यदि किसी व्यक्ति को ऐसी पहुंच मिली थी तो उसका अधिकार किस आदेश से तय हुआ? याचिकाकर्ताओं ने डिजिटल ऑडिट ट्रेल का भी ब्यौरा मांगा है। किस यूजर ने बदलाव किया किस तारीख और किस समय किया, किस आदेश के आधार पर किया और किस अधिकारी ने उसे मंजूरी दी? क्या किसी मतदाता का नाम निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के आदेश के बिना सिस्टम स्तर पर हटाया या बदला जा सकता था? क्या बड़ी संख्या में नाम एक साथ हटाने या डेटा माइग्रेशन की कोई प्रक्रिया अपनाई गई?

सवाल नम्बर एक- देशव्यापी एसआईआर का फैसला किसने लिया?

48 सवालों में सबसे बुनियादी सवाल यही है कि पूरे देश में एसआईआर कराने का फैसला आखिर कब और किस प्रक्रिया से लिया गया? याचिकाकर्ताओं ने 24 जून 2025 के आदेश का हवाला देते हुए पूछा है कि जब आयोग ने पूरे देश में एसआईआर शुरू करने की बात कही, तो उसके पीछे कौन-सी आधिकारिक फाइल थी? फैसला किस तारीख को हुआ? क्या तीनों आयुक्तों ने बैठक में मंजूरी दी या फाइल उनके पास अलग-अलग भेजी गई? विपक्ष ने एक और विरोधाभास की ओर ध्यान दिलाया है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक अगस्त 2025 में आरटीआई के जवाब में आयोग की ओर से ऐसी सूचना दी गई थी कि देशव्यापी एसआईआर शुरू करने के फैसले से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब सवाल है कि यदि जून में आदेश जारी हुआ था तो अगस्त में आरटीआई के जवाब में यह जानकारी क्यों उपलब्ध नहीं थी? किस स्तर पर निर्णय दर्ज किया गया था? क्या फाइल मौजूद है? और यदि मौजूद है तो अदालत के सामने क्यों नहीं रखी गई?

सवाल नम्बर पांच- नाम हटे कितने, कारण क्या और जिम्मेदार कौन?

विपक्ष ने एसआईआर के दौरान मसौदा और अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए नामों का राज्यवार ब्यौरा भी मांगा है। कितने नाम मृत्यु के कारण हटाए गए? कितने मतदाता दूसरी जगह चले गए? कितने अनुपस्थित पाए गए? कितने नाम दोहराव या अपात्रता के आधार पर हटाए गए? यहां सिर्फ कुल संख्या जानना पर्याप्त नहीं है। यह भी जरूरी है कि हर श्रेणी के पीछे सत्यापन की प्रक्रिया क्या रही। यदि किसी मतदाता का नाम गलती से हट गया तो उसे वापस जोड़ने की व्यवस्था कितनी आसान थी? क्या ईसीआईनेट पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के पास हटाए गए नाम बहाल करने का विकल्प उपलब्ध था? यदि किसी अवधि में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो वह कितने समय तक बंद रही?

जनसमर्थन के लिए कथा करा रहे हैं, लेकिन अपना काम नहीं बता पा रहे हैं: अखिलेश

» राजा भैया के रामकथा आयोजन पर सपा प्रमुख का तंज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। कुंडा में राजा भैया की ओर से आयोजित रामकथा को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि लोग कथा करा रहे हैं, लेकिन जनता को अपना काम नहीं बता पा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट पर आयोजित हो रही रामकथा को लेकर सियासत गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के इस आयोजन पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग कथा करा रहे हैं, लेकिन जनता को अपना काम नहीं बता पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनसमर्थन हासिल करने के लिए कथा का सहारा लिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान राजा भैया के आयोजन और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रमों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो लोग जनता को अपना काम नहीं बता पा रहे हैं, वे अब जनसमर्थन जुटाने के लिए कथा का सहारा ले रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि कथा करने वाले तो कथा सुनाकर चले जाएंगे, लेकिन आयोजकों को यहीं रहना है।

दरअसल, प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बेती राजभवन परिसर में 17 से 20 नवंबर तक चार दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह आयोजन राजा भैया के संसाधनों से कराया जा रहा है।

धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा को लेकर जताया एतराज

अखिलेश यादव ने इस धार्मिक आयोजन और धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रमों पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे आयोजनों को रोकने की मांग भी की है। उनका आरोप है कि इन आयोजनों से भावनाएं आहत हुई हैं।



राजा भैया बोले- रामकथा कभी विवादित नहीं हो सकती

अखिलेश यादव की टिप्पणी और आयोजन को लेकर हो रही राजनीतिक बयानबाजी पर राजा भैया ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रामकथा कभी विवादित नहीं हो सकती। राजा भैया ने स्पष्ट किया कि इस आयोजन का 2027 के विधानसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। यह पूरी तरह से एक धार्मिक अनुष्ठान है। वहीं, अखिलेश यादव ने अपने बयान में संविधान और आरक्षण की रक्षा करने की बात भी दोहराई।



मेरे एवीबीपी में होने के आरोप अगर सही हुए तो राजनीति छोड़ दूंगा

» सांसद : चंद्रशेखर आजाद बोले- किसी भी पत्रकार को इस तरह से बिना किसी सबूत के आरोप नहीं लगाने चाहिए

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद राज्य में सियासी घमासान मचा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद (रावण) ने अपने कॉलेज के दिनों में अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एवीबीपी) से की थी।



ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने अब इन दावों का खंडन किया है. उन्होंने इन दावों को खारिज करते हुए कहा, मेरे एवीबीपी में होने के आरोप अगर सही हुए तो राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने आगे कहा, जनता जिनको वोट दे रही है. अगर उनके मन में कोई भी शिकवा, सवाल गया तो उसका जवाब नेताओं को देना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने एक इंटरव्यू में कहा, एक पत्रकार ने टीवी डिबेट में आरोप लगाए. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पास क्या सोर्स है जो आरोप उन्होंने लगाए और बड़ी जिम्मेदारी से लगाए. अगर उनके आरोप गलत हुए तो उनको टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने यह जवाब क्यों दिया, किसके कहने पर दिया मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। चंद्रशेखर ने आगे कहा, वो डीएवी कॉलेज आज भी है और उसमें आज भी चुनाव होते हैं, किसी भी पत्रकार को इस तरह से बिना किसी सबूत के आरोप नहीं लगाने चाहिए. मेरा यह मानना है कि कोई भी बात अगर सामने आई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, वह इसकी रिसर्च करें. वह सभी लोग जो इस तरह के बयान दे रहे हैं. वह देहरादून जाकर मेरे साथ वालों और जानकारों से पूछताछ कर लें। भीम आर्मी चीफ ने कहा, रिसर्च में उन्हें पता चल जाएगा कि मैं किस ग्रुप से जुड़ा रहा, मेरी राजनीतिक पहचान और विचार क्या है. यह उन्हें पता लग जाएगा, लेकिन जो उन्होंने किया उससे स्पष्ट हुआ कि भारतीय मीडिया जो है बिना रिसर्च के बहुत सारे बयान किसी को फायदा पहुंचाने और किसी का नुकसान करने के लिए देता है।

अजय माकन को यूपी चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी में स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सेवादल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक बी. वी. श्रीनिवास और महाराष्ट्र से असलम शेख को को भी सदस्य के रूप में कमेटी में शामिल किया गया है।



यह कमेटी चुनाव में प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत के लिए कांग्रेस ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, राजेंद्र पाल गौतम, इमरान मसूद और मोना तिवारी शामिल हैं। यह समिति तय करेगी कि कांग्रेस को कितनी और कौन सी सीटें मांगनी चाहिए। एक अहम बैठक में कांग्रेस ने साफ किया कि वह सपा से केवल उन्हीं सीटों की मांग करेगी, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा था। बैठक के बाद खरगे ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव राज्य की जनता को एक मजबूत विकल्प देंगे। कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन की जिम्मेदारी निभाएगी।

सपा प्रमुख के आगरा में पीडीए-दलित सम्मलेन में खाली रहीं कुर्सियां: शादाब

» एआईएमआईएम ने सपा पर किया प्रहार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगमी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के गठन के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक गहमा-गहमी तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा, सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के गठन के बाद समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, कांग्रेस और बीजेपी के साथ सब बौखलाए हुए हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे पास एक समीकरण है कि कैसे सत्ता को प्राप्त करके ये वंचित, पीड़ित, शोषित वर्ग के लोग मुसलमान, दलित, पिछड़े अपनी सरकार बनाकर अन्याय को समाप्त कर सकते हैं। शादाब चौहान ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आगरा में पीडीए-दलित सम्मलेन पर तंज कसते हुए कहा, वहां हमारे दलित भाइयों ने संकेत दे दिया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, कार्यक्रम में कुर्सियां खाली पड़ीं थीं, क्योंकि दलित, मुस्लिम, पीड़ित वंचित वर्ग से सामजिक परिवर्तन मोर्चे में अपना विश्वास जता चुका है और भाई चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर चुका है।



अखिलेश यादव को गठबंधन का न्योता

शादाब चौहान ने आगे कहा कि अखिलेश जी बौखला गए हैं और इधर-उधर की बातें करने लगे हैं. वो मेरे नेता पर सवाल करने लगे, तो याद रख लीजिए कि बीजेपी को हारने के लिए हमारे नेताओं के दरवाजे आपके लिए खुले हैं. लेकिन आप अगर जनता को गुमराह करेंगे, अगर उनको अपना सियासी गुलाम और राजनीतिक अछूत समझेंगे, तो उत्तर प्रदेश का दलित, पीड़ित, शोषित और मुसलमान आपको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है. आपका राजनैतिक रूप से सफाया हो जाएगा अगर आपने सही फैसला नहीं लिया.

नाथवानी को राज्यसभा भेजने पर सवाल

रूप्रवक्ता ने अखिलेश यादव पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर आपकी डोर बीजेपी के हाथ में नहीं तो आपने क्यों धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा भेजा. आजम खान को लेकर सवाल उठाया कि जांच सिर्फ आजम खान और उनके परिवार की होती है आपकी क्यों नहीं ? इसके साथ ही अखिलेश यादव के अयोध्या जाने पर सवाल खड़ा करते हुए कहा,आप अयोध्या 12 दिसम्बर को क्यों जा रहे हैं ? क्या वो भारत के संविधान पर हमला नहीं था ? क्या साबित करने के लिए जा रहे हैं, क्या प्रमाणित करने के लिए जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दलों का नहीं दिलों का मिलन है इसलिए सपा और भाजपा के खेमे में जलन है।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी



पंजाब में 2027 चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ेगी आप: मान

» मुख्यमंत्री ने तरनतारन में किया एलान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी (आप) के ''सुशासन के एजेंडे और पूर्ववर्ती सरकारों की राजनीति'' के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए सोमवार को कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव जनकल्याण, विकास और ठोस परिणामों के मुद्दों पर लड़े जाएंगे।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मान ने कृषि क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया, जिनमें नहर के पानी का उपयोग 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 88 प्रतिशत करना और 14,000 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना शामिल है। इसके साथ ही, उन्होंने सामान्य परिवारों के बच्चों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) का अधिकारी बनने में मदद करने के लिए नि:शुल्क कोचिंग केंद्र खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता पंजाब के भीतर ही रोजगार और शिक्षा के अवसर पैदा करना है ताकि राज्य के युवाओं को विदेश पलायन करने के लिए मजबूर न होना पड़े। पट्टी विधानसभा क्षेत्र के सभरा गांव में 'लोक मिलनी' (जनसंवाद) कार्यक्रम के दौरान मान ने सख्त 'जागत जोत सत्कार संशोधन अधिनियम' के माध्यम से धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और विश्वास जताया कि माझा क्षेत्र के लोग 2027 में 'आप' को प्रचंड जनादेश देंगे। माझा क्षेत्र में तरनतारन और अमृतसर जैसे जिले शामिल हैं।



एक सभा को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि 'लोक मिलनी' कोई राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन, चिंताओं और आकांक्षाओं पर चर्चा करने का एक अवसर है।

छठ पूजा पर सियासी बयान, मचा घमासान

बोले राजठाकरे, कल्याण बनर्जी व वारिस पठान, विपक्ष के बोल से तिलमिलाई भाजपा



» छठ पर सबसे ज्यादा विवाद महाराष्ट्र व बंगाल में

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। छठ पूजा अब बिहार की सीमा से बाहर निकल कर देश दुनिया में पहुंच चुकी है। इसको लेकर सियासत भी चरम पर है। छठ पर सबसे ज्यादा विवाद महाराष्ट्र व बंगाल में हो रहा है। जहां बंगाल में टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी छठ पूजा पर भड़के हैं जिसकी वजह से भाजपा भी आग बबूला हो गई है।

कल्याण ने कहा बंगाल, बंगालियों का राज्य या उपद्रवी बिहारियों का। महाराष्ट्र में राज ठाकारे व वारिस पठान के छठ पर दिए बयान के बवाल मच गया है। पश्चिम बंगाल में कल्याण बनर्जी ने छठ पूजा की व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए एक विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल पर अब गैर-बंगालियों का कब्जा हो गया है। उन्होंने पूछा, क्या पश्चिम बंगाल बंगालियों का है या बिहारियों का? उन्होंने छठ पूजा की व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की। आरोप लगाया कि बंगाल पर अब गैर-बंगालियों का कब्जा हो गया है और सत्ताधारी पार्टी बंगाली संस्कृति को कमजोर कर रही है। कल्याण बनर्जी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन पर त्योहार के लिए की गई सजावट के पैमाने पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्गा पूजा के दौरान ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई थीं। उन्होंने बिहारियों पर बंगाल पर कब्जा करने का आरोप लगाया। वहीं कल्याण बनर्जी के बयान पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।



राज्य में बंगाली अब दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए हैं : कल्याण

टीएमसी नेता ने आगे आरोप लगाया कि राज्य में बंगाली अब दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यही स्थिति अगले पांच साल तक बनी रही, तो बंगालियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बीजेपी ने उन्हें निशाने पर लिया और ममता बनर्जी पर सवाल उठाए। कल्याण बनर्जी ने छठ पूजा पर कहा कि क्या पश्चिम बंगाल में अब बंगाली बचे भी हैं? क्या पश्चिम बंगाल बंगालियों का है या उपद्रवी बिहारियों का? क्या सनातन धर्म का पालन करने का मतलब बंगालियों को किनारे करना और बिहारियों को स्थापित करना है? भाजपा बंगाली संस्कृति को नष्ट कर देगी। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि छठ के लिए हावड़ा स्टेशन को इस तरह सजाया गया है। दुर्गा पूजा के लिए ऐसी सजावट नहीं की जाती।



हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा का आयोजन करने के लिए मना किया था

हाई कोर्ट ने भी सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा का आयोजन करने के लिए मना किया था। इसकी वजह से कुछ लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन लोगों को समझ ना चाहिए कि दिवाली और खराब वायु प्रदूषण के बीच लोगों के स्वास्थ्य और तबीयत को प्राथमिकता देनी होगी। आपकी आस्था अपनी जगह सही है, उसपर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा लेकिन ऐसा कुछ न करें जिससे शहर के लोगों की सेहत पर असर पड़े। कुछ निर्धारित जगहों पर कड़े नियमों के तहत पूजा किया जाना ठीक है।

शुभेंदु अधिकारी ने व्यवस्थाओं का किया बचाव

शुभेंदु अधिकारी ने भी त्योहार के लिए सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं का बचाव किया। उन्होंने छठ को सनातन परंपरा का उत्सव बताया और इसे किसी एक समुदाय या राज्य तक सीमित करने की कोशिशों को खारिज कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा के रामकृष्णपुर घाट पर छठ पूजा के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा को मानने वाले कम से कम एक करोड़ लोग इस त्योहार को मना रहे हैं, और इसमें केवल हिंदी भाषी लोग ही शामिल नहीं हैं। सनातन परंपरा को मानने वाले कम से कम एक करोड़ लोग इसे मना रहे हैं। इसमें सिर्फ हिंदी भाषी ही नहीं, बल्कि सनातन परंपरा को मानने वाले सभी लोग शामिल हैं। छठ आस्था और परंपरा का एक भव्य त्योहार है। सरकार ने दुर्गा पूजा, काली पूजा और दिवाली की तरह ही छठ के लिए भी व्यवस्थाएं की थीं, और त्योहार के लिए दी गई सुविधाएं काफी व्यवस्थित थीं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वे दावा करेंगे कि गणपति उत्सव सिर्फ मराठियों का है, छठ सिर्फ बिहार के लोगों का है, या राम नवमी सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने इस तरह के बंटवारे को नकार दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि आखिरकार, हम सब भारतीय हैं। देश भर में छठ का उत्सव मनाया जाता है।

राहुल गांधी हमेशा से सही कहते आ रहे हैं : माजिद

वहीं, राहुल गांधी के पक्ष में भी माजिद मेमन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा, मैं खुद राज्यसभा में था। मैंने देखा है कि कैसे सरकारी संस्थाओं को काबू में कर रखा है। राहुल गांधी हमेशा से सही कहते आ रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। दरअसल, राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि साल 2014 में भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। हैदराबाद में भारत समिट में राहुल गांधी के सामने इटली के नेता के नारे पर भी विवाद हुआ। इटली के नेता ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया था। इसपर बीजेपी बोली कि राहुल गांधी देश की संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।



टीएमसी बांटने वाली राजनीति कर रही : इंद्रनील खान

कल्याण बनर्जी के बयान पर पश्चिम बंगाल के मंत्री इंद्रनील खान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने टीएमसी पर बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया और बंगाली संस्कृति तथा लोगों से जुड़े मुद्दों पर पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। इंद्रनील खान ने आरोप लगाया कि न तो पिछली TMC सरकार और न ही वामपंथी (लेफ्ट) सरकार ने बंगाली लोगों के हितों के लिए कोई ठोस काम किया है। उन्होंने पूछा कि क्या मां काली को पुलिस की गाड़ी (प्रिजन वैन) में ले जाना बंगाली संस्कृति है? क्या मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन को रोकना बंगाली संस्कृति है? क्या दरीभीत में बंग ला भाषा के शिक्षक की नियुक्ति की मांग कर रहे छात्रों पर गोलियां चलाना बंगालियों के हित में था? वे सिर्फ बांटने वाली राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। अगर उन्होंने सच में बंगालियों के हित में काम किया होता, तो TMC के 15 साल और वामपंथियों के 34 साल के शासन में बंगाल की स्थिति काफी बेहतर होती।



मुसलमान रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने लगे तो बवाल होगा : पठान



छठ पर्व पर महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों पर बज रहे गीतों को लेकर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने टिप्पणी की थी। उन्होंने भोजपूरी गीत बजने पर आपत्ति नहीं जताई थी, बल्कि नियमों की समानता पर सवाल उठाए थे, वारिस पठान ने कहा था कि अपना पर्व मनाने का हक सबको है, लेकिन अगर मुसलमान रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने लगे तो बवाल होगा इसपर अब पूर्व राज्यसभा सांसद माजिद मेमन की प्रतिक्रिया आई है। माजिद मेमन ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव को देखते हुए ऐसे बयान देकर हर कोई सुर्खियों में रहना चाहता है। मुझे नहीं लगता की एआईएमआईएम खुद सच में चाहेगी कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर नमाज पढ़ा जाए। इससे लोगों को दिक्कतें होंगे।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_SanjayS

जिद... सच की

छोटे-छोटे स्कूली बच्चे क्यों हो रहे हिंसक

देश के अलग-अलग हिस्सों से छोटे-छोट स्कू ली बच्चों में आपसी मार-पीट खबरें स्तब्ध करने वाली है। गत दिनों लखनऊ, पंचकूला समेत कई शहरों में ऐसे हादसे सुर्खियां बनीं। पंचकु लस में एक सरकारी स्कूल में आठ साल के छात्र ने अपनी छह साल की सहपाठी की बेरहमी से पिटाई कर दी। बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई और उसे पीजीआई, चंडीगढ़ में भर्ती कराना पड़ा। घटना के बाद स्कूल की प्रिंसिपल और दो शिक्षकों को निलंबित किया गया तथा प्रिंसिपल, एक क्लास इंचार्ज और चौकीदार के खिलाफ लापरवाही की एफआइआर दर्ज हुई। घटना की वजह जांच से सामने आएगी, इसलिए कयास लगाना ठीक नहीं। लेकिन इसने एक सवाल जरूर खड़ा किया है। बच्चों के बीच हिंसा की जगह कैसे बन रही है? क्या इसका जवाब सिर्फ उस बच्चे, उसके माता-पिता या स्कूल को जिम्मेदार ठहराने में मिल जाएगा? बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा का 1961 में किया गया बोबो डॉल प्रयोग उपयोगी है। इसमें बच्चों ने एक वयस्क को खिलौने के साथ आक्रामक व्यवहार करते देखा और बाद में कई बच्चों ने वैसा ही व्यवहार दोहराया। इसका मतलब यह नहीं कि हिंसक फिल्म या वीडियो गेम देखने वाला हर बच्चा हिंसक हो जाएगा, लेकिन आसपास का व्यवहार असर जरूर छोड़ता है। घर में बड़ों का गुस्सा, फिल्मों और वीडियो गेम्स में दिखाई जाने वाली हिंसा और सोशल मीडिया पर मारपीट के वीडियो, बच्चा इन सबको देख रहा होता है। आज सवाल सिर्फ स्क्रीन टाइम का नहीं, स्क्रीन पर दिखने वाली चीजों और उन्हें बार-बार सामने लाने वाले एल्गोरिदम का भी है। बच्चा किसी हिंसक वीडियो को देर तक देखता है या उससे जुड़े वीडियो पर रुकता है, तो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम इसे उसकी रुचि का संकेत मान सकता है। इसके बाद उसकी फीड में उसी तरह के और वीडियो आने लगते हैं। धीरे-धीरे बच्चे को खुद भी पता नहीं चलता कि कब वह इस तरह के कंटेंट को बार-बार देखने का आदी हो गया। इसी चिंता के बीच ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लागू की। इस मॉडल में कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी बच्चों या उनके माता-पिता के बजाय सोशल मीडिया कंपनियों की है। कंपनियां जरूरी कदम नहीं उठातीं, तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं के वीडियो बार-बार न दिखाए।हर झगड़ा या मारपीट बुलिंग नहीं होती। बुलिंग तब होती है जब किसी बच्चे को बार-बार निशाना बनाया जाए, डराया या अपमानित किया जाए और ऐसा करने वाला अपनी ताकत या समूह का इस्तेमाल करे। शरीर, रंग, भाषा, परिवार या पढ़ाई को लेकर लगातार चिढ़ाना भी बुलिंग है। ऑनलाइन बार-बार अपमानित करना या धमकाना साइबर बुलिंग कहलाता है। इसमें आसपास खड़े बच्चों की भूमिका भी अहम होती है।

“ बच्चों के बीच हिंसा की जगह कैसे बन रही है? क्या इसका जवाब सिर्फ उस बच्चे, उसके माता-पिता या स्कूल को जिम्मेदार ठहराने में मिल जाएगा? बच्चा किसी हिंसक वीडियो को देर तक देखता है या उससे जुड़े वीडियो पर रुकता है, तो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम इसे उसकी रुचि का संकेत मान सकता है। इसके बाद उसकी फीड में उसी तरह के और वीडियो आने लगते हैं। धीरे-धीरे बच्चे को खुद भी पता नहीं चलता कि कब वह इस तरह के कंटेंट को बार-बार देखने का आदी हो गया।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

एक भारतीय प्रेम कहानी और राजनीतिक निहितार्थ

ज्योति मल्होत्रा

सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग' भारत में व्यापक सुर्खियों में बनी हुई है। निश्चित ही, आप इस किताब विशेष की विषयवस्तु इसके मुखपृष्ठ से ही जान जाते हैं। इस पर एक युवा यूरोपीय महिला की श्वेत-श्याम तस्वीर है-जो अपने प्यार की खातिर आधी दुनिया पार कर भारत आई और उसके गुजर जाने के बाद भी यहीं बनी रही। वह तब भी डटी रही, जब विपक्ष और उसकी अपनी ही पार्टी के साथी विदेशी मूल होने को लेकर उस पर तंज कसते रहे। यह तस्वीर वाकई बहुत खूबसूरत है।

इतना ही नहीं, किताब में नाकाबिल-ए-माफी 55 त्रुटियों के बावजूद-स्पष्टत: जो खराब संपादन की वजह से बच निकलीं-ऐसा लगता है कि इस किताब ने गांधी परिवार और कांग्रेस को एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है। निश्चित ही, कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे पार्टी को एक नई जान मिलेगी, जो मौजूदा राजनीति से इतर बनी रहेगी। वह भी ऐसे समय में, जब पांच अहम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जो देश की राजनीति का स्वरूप बदल सकते हैं।

ऐसा लगता है कि शायद किताब के माध्यम से बेहतरीन संवाद बनाने की पुरजोर कोशिश की गई है। यह उच्च कोटि की कहानियों के प्रति भारतीयों के प्रेम की पर्याय है, यानी 'कथासरित्सागर' यानी कहानियों का महासागर। वह जिसका उपयोग करते हुए सलमान रुश्दी ने कुछ दशक पहले अपनी रचनाएं अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया के सामने पेश की थीं। अटल बिहारी वाजपेयी को भी इसका उपयोग अपनी हिंदी कविताओं और चुटीले अंदाज से करने की समझ थी। शायद इसीलिए देश उन्हें बहुत प्यार करता था, भले ही उन्होंने हमेशा बीजेपी को वोट न दिया हो। सोनिया की यादों का पिटारा रूपी इस पुस्तक में एक बहुत ही प्यारा किस्सा है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक बार वाजपेयी ने सोनिया को समझाया था कि भले ही कांग्रेस और बीजेपी राजनीतिक रूप से एक-दूसरे के विरोधी हों, फिर भी राजनीति से इतर दोनों पक्षों के बीच एक रिश्ता सदा कायम रह सकता है। सालों बाद, जब वाजपेयी एक बार गंभीर रूप से अस्वस्थ हुए और सोनिया उनका हाल-चाल पूछने गईं, तो उन्होंने बिना कुछ



कहे बस अपना हाथ बढ़ाया और सोनिया का हाथ थाम लिया।

आप सोनिया की किताब को ब्लिंकइट पर भी ऑर्डर कर सकते हैं—यह भी उनकी राजनीतिक रणनीति का ही एक हिस्सा है। पुस्तक विक्रेताओं तक किताब पहुंचने से कुछ दिन पहले ही, कांग्रेस की इस वरिष्ठ नेता की पुस्तक का विमोचन इंस्टाग्राम पर भी हुआ। इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी की लोकप्रियता की तुलना में वे अभी काफी पीछे हैं-पिछले तीन हफ्तों में उनके केवल 3,55,000 फॉलोअर्स हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री के अकाउंट के 10.7 करोड़ फॉलोअर्स हैं। किताब का मंतव्य भारत के सबसे पुराने राजनीतिक वंश की जटिल और अक्सर विरोधाभासी कहानियों को देश के विशाल युवा वर्ग तक पहुंचाना है। यह तमाम कोशिशें बिक्री कला की उस पुरानी कहावत को सच साबित करती हैं कि प्रचार अच्छा हो या बुरा, आखिर प्रचार तो प्रचार ही होता है। एक 'भारतीय प्रेम कहानी' से बेहतर और क्या हो सकता है, जिसकी मुख्य नायिका 'भारत माता' हो और जिसके किरदार दुनिया के अलग-अलग हिस्सों और विभिन्न धर्मों से जुड़े हों?

इसका कतई यह मतलब नहीं है कि यह किताब कांग्रेस पार्टी को उन राज्यों के चुनावों में कोई फायदा पहुंचाएगी, जहां वह फिलहाल चुनावी मैदान में है। हालांकि, जैसा कि हम जानते हैं, अतीत कभी पूरी तरह से अतीत नहीं बनता; वह अक्सर वर्तमान में आ खड़ा होता है। यह बात पंजाब के लिए उतनी ही सच है, जहां आज भी 1984 के सिख-विरोधी दंगों की भयावह यादें ताज़ा हैं; और उत्तर प्रदेश के लिए भी, जिसने राम मंदिर बनाने के वादे पर बार-बार बीजेपी को सत्ता में पहुंचाया—और अब सवाल यह है कि क्या अयोध्या के मंदिर में हुई चोरी की घटना इसके राजनीतिक भाग्य पर कोई असर डालेगी?

पंजाब और दिल्ली में, सोनिया गांधी द्वारा 1984 के 'नरसंहार' को 'दुखद और शर्मनाक' बताए जाने से काफी हलचल हुई है। बीजेपी ने सिख-विरोधी दंगों में अपने पति खोने वाली कुछ विधवाओं को गुरुद्वारा रकाब गंज में इकट्ठा किया, ताकि वे अपनी आपबीती सुना सकें कि कैसे दंगे भड़काने के दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की कुछ महीने पहले जेल में मौत हो जाने के बावजूद, प्रभावित 2,800 परिवारों में से किसी को भी आज तक सही मायने में न्याय नहीं मिला है।

कांग्रेस पार्टी ने 1984 के दंगों के लिए कभी औपचारिक रूप से माफी नहीं मांगी है। 11-12 अगस्त 2005 को, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में करीब-करीब माफी जैसा बयान जरूर दिया था। यह बयान नानावती आयोग की रिपोर्ट पेश किए जाने के तुरंत बाद आया था, जिसका गठन पांच साल पहले, वर्ष 2000 में, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 1984 के दंगों के कारणों, उनके दायरे और घटनाओं के क्रम की जांच के लिए किया था। डॉ. सिंह ने कहा था 'इन दुखद घटनाओं ने देश की अंतरात्मा को गहरा घाव दिया है और संविधान में निहित 'भारतीय राष्ट्र' की अवधारणा को नकारा है।

अग्निपथ योजना में बदलाव का सही समय

अरुण प्रकाश, पूर्व नौसेनाध्यक्ष



लागू होने के चार साल बाद, अग्निपथ योजना के समक्ष पहली बड़ी चुनौती बनी, और सरकार ने चुपचाप नीति में बदलाव कर दिया। गत 4 नवंबर को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निवीरों की सेवा अवधि में दो साल के विस्तार को मंजूरी दे दी। चार साल का अनुबंध पूरा होने के बाद, जो अग्निवीर योग्यता के आधार पर शीर्ष 25 फीसदी में नहीं आ पाएंगे, उन्हें बतौर नियमित सैनिक शामिल होने का एक और मौका मिलेगा। अगर तो यह वास्तव में योजना को वापस लेने की शुरुआत है, तो स्वागतयोग्य है। लेकिन चार साल बाद ऐसा बदलाव होने पर वह सवाल उठता है जिसका उत्तर 2022 में कभी सही नहीं दिया गया था। सर्वप्रथम, एक समयसिद्ध, सफल व अच्छी तरह स्थापित प्रणाली इतनी जल्दबाजी में क्यों बदली जा रही है?

14 जून, 2022 को प्रेस सूचना ब्यूरो के एक नोट में कहा गया कि इस योजना से 'सशस्त्र बलों का चेहरा युवा रहेगा', 'नया जोश और जज्बा भरेगा' व सेना 'और अधिक तकनीक-कुशल' बनेगी। इसमें देशभक्ति, टीमवर्क, शारीरिक फिटनेस व देश के प्रति निष्ठा जैसे लाभों का भी जिक्र किया गया था।

उक्त 'तर्कों' में से एक भी भर्ती की एक स्थापित प्रणाली, बुनियादी प्रशिक्षण व सैनिकों को चरणबद्ध रूप से शामिल करने की व्यवस्था को ध्वस्त करके, उसकी जगह एक ऐसी योजना लाने को न्यायोचित नहीं ठहराती, जिसे पहले कभी आजमाया नहीं हो और जो मूलत: त्रुटिपूर्ण है। जिन्होंने भर्ती रैलियां देखी हैं या उनके बारे सुना है, वे जानते हैं कि हमारे देश के युवाओं में जोश-जज्बे की कोई कमी नहीं; वे हजारों की संख्या में सेना में शामिल होने आते हैं। हमारी रेजिमेंटों, युद्धपोतों और स्क्वाड्रनों में नियुक्त फौजियों में देशभक्ति, टीमवर्क और फिटनेस पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। साथ ही, 'देश के प्रति वफादारी' पैदा करने का तर्क इतना भी मजबूत नहीं कि इसके लिए कोई ऐसा उपाय किया जाए, जो दीर्घकाल में सशस्त्र बलों के मूल ढांचे पर ही असर डाल दे।

भर्ती की औसत उम्र की घटाना एक अच्छा लक्ष्य लग सकता है, लेकिन उम्र का सीधा संबंध युद्ध लड़ने की क्षमता से नहीं होता। यह क्षमता कौशल से बनती है, और कौशल हासिल करने में समय लगता है। ज्यादातर देहात से आने वाले और हमारी त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली से निकले नए रंगरूटों के लिए चार से छह महीने का बुनियादी प्रशिक्षण नाकाफी है। किसी सैनिक, नाविक या वायुसैनिक को जटिल और महंगे युद्धक उपकरण या हथियार सौंपना या उसको असल युद्ध जैसी स्थितियों में उतारने से पहले, दो-तीन साल का व्यावहारिक एवं काम के दौरान अनुभव पाने हेतु प्रशिक्षित करना अनिवार्य है।

हो सकता है कि कोई नया रंगरूट स्मार्टफोन चलाने में माहिर हो, लेकिन रडार, फायर-कंट्रोल सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल, एयरो-इंजन या साधारण डीजल जनरेटर कैसे काम करते हैं, यह समझने और एक कुशल 'ऑपरेटर' बनने की महारत के लिए उसे महीनों प्रशिक्षण की जरूरत होगी। इन्हें प्रशिक्षित होने में और ज्यादा समय लगता है। इन सबके ऊपर 'उस्ताद' होते हैं, जिनका दशकों का अनुभव होता है और ये उस्ताद अधिकारियों सहित सबको सिखाते हैं। साढ़े सत्रह साल की उम्र में भर्ती होने वाले हर सैनिक को सिखाने के लिए, सेनाओं को अनुभवी और युद्ध से तपे सूबेदार मेजर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर और मास्टर वारंट ऑफिसर की जरूरत होती है, जो 54-56 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। अगर आप इस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो कहीं न कहीं कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इसका उदाहरण नौसेना में देखने को मिला, जिसने 2022 में अपना 'आर्टिफिसर कैडर' खो दिया, वह इकाई जो नौसेना के हथियार, सेंसर और मशीनरी के रखरखाव की आपूर्तिकर्ता होती है।

अग्निपथ योजना के तहत, चार साल के कार्यकाल में से अगर बुनियादी प्रशिक्षण, वार्षिक छुट्टी और सेवामुक्त होने से पहले की अवधि घटा दें, तो एक सैनिक की वास्तविक उपलब्धता लगभग तीन साल ही बचती है। इससे कुछ परेशानीकारक सवाल उठते हैं। क्या सेना ऐसे व्यक्ति को तकनीकी स्किल सिखाने में निवेश करना चाहेगी,जिसकी नौकरी जल्द ही खत्म होने वाली हो? क्या अग्निवीर खुद भी इन कौशलों को सीखने में दिलचस्पी लेगा, जब उसका आगे बने रहना ही पक्का न हो? योजना के तथाकथित लाभ दोनों ही पक्षों के लिए गलत दिशा की ओर इंगित करते हैं। चाहे यह विचार सेना मुख्यालय से आया हो या रक्षा मंत्रालय ने थोपा हो, इतने बड़े बदलाव को पहले एक 'पायलट प्रोजेक्ट' के रूप में आजमाना चाहिए था-यानी इसे किसी एक या अधिक सैन्य यूनिटों में प्रयोग किया जाता, या बेहतर होगा कि 'टेरिटोरियल आर्मी' में लागू कर देखा जाता और फिर परिणामों का विश्लेषण किया जाता। इसके बजाय, पूरी सशस्त्र सेना पर अचानक इस जोखिम भरे प्रयोग को लाद दिया गया।

हालांकि सरकार लगातार यह कहती रही है कि इसके पीछे कोई वित्तीय मकसद नहीं, लेकिन लगभग तय है कि अग्निवीर योजना रक्षा मंत्रालय के बढ़ते 'कार्मिक खर्चे' को नियंत्रित करने से चालित है, क्योंकि सब खर्चों के बाद,हथियारों और उपकरणों की खरीद के लिए उपलब्ध फंड में कमी आ जाती है। तथापि, पेंशन खर्च मद में बचत किए जाने की एवज में रक्षा क्षमताओं से समझौता करना बहुत बुरा सौदा है।

बच्चे को पांच साल तक ये चीजें न खिलाएं

हम क्या चीजें खाते-पीते हैं इसका सेहत पर सीधा असर होता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को ऐसी चीजें ज्यादा खाने की सलाह देते हैं जिससे आवश्यक पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति हो सके। जब बात बच्चों की सेहत की हो तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चे जो कुछ भी खाते-पीते हैं, उसका असर सीधे उनके विकास, हड्डियों की सेहत, दांतों और पाचन तंत्र पर पड़ता है। यही वजह है कि पांच साल से कम उम्र में खाने-पीने की चीजों को लेकर सावधानी और भी जरूरी हो जाती है। कई चीजें वयस्कों के लिए सामान्य हो सकती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए वही खाना दम घुटने, पेट खराब होने, दांतों की समस्या बढ़ाने वाला बन सकता है। ऐसी चीजें जो बहुत सख्त, गोल, चिपचिपी या छोटे आकार की हों, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिमों को और भी बढ़ाने वाली हो सकती हैं।

बादाम, मूंगफली और काजू



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, छोट बच्चे खाने वाली चीजों को ठीक तरीके से चबाते नहीं हैं, इसलिए कोई भी सख्त चीज उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली और कई बार गले को चोक करने वाली हो सकती हैं। बादाम, मूंगफली, काजू जैसे मेवे छोटे बच्चे चबाने की जगह घोंट जाते हैं जिससे घुटन का खतरा पैदा हो सकता है। बच्चों को अगर आपको ये मेवा खिलानी है तो आप बादाम, मूंगफली और काजू को अलग-अलग भूनकर उनका बारीक पाउडर बना सकते हैं। इस पाउडर की आधी छोटी चम्मच मात्रा को आप बच्चे की सूजी की खीर, दलिया, ओट्स या प्यूरी में मिलाकर दे सकते हैं। वहीं 3 साल के बच्चे को आप उन्हें नट बटर (जैसे- पीनट बटर या आलमंड बटर) ब्रेड या रोटी पर लगाकर दे सकते हैं। इसके अलावा, भीगे हुए बादाम का छिलका उतारकर और उसे पीसकर दूध में मिलाकर दिया जा सकता है। वहीं 3 साल से बड़े जब बच्चे अच्छी तरह चबाना सीख जाएं, तब आप उन्हें भीगे हुए बादाम, काजू के छोटे टुकड़े या भुनी हुई मूंगफली सीधे खाने के लिए दे सकते हैं।



आहार में ज्यादा चीनी

छोटे बच्चों को मिठाई, मीठे पेय, बिस्किट और चीनी वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थ भी बार-बार देने से बचना चाहिए, ये शरीर में ऐडेड शुगर को बढ़ाने वाली हो सकती हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स दो साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी चीनी वाली चीजें न देने की सलाह देता है। मीठे पेय दांतों की सड़न बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इनमें मौजूद ज्यादा कैलोरी बच्चों में मोटापे की दिक्कत भी बढ़ाने वाला हो सकता है।

कच्चा दूध या पनीर

छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अभी विकसित हो रही होती है, इसलिए दूषित भोजन से होने वाला संक्रमण उनके लिए ज्यादा गंभीर हो सकता है। अधपका मांस या अंडा, बिना पाश्चराइज किया दूध या पनीर और बिना धोए फल-सब्जियां संक्रमण का जोखिम बढ़ा सकते हैं। बच्चों को हमेशा अच्छी तरह पका और सुरक्षित भोजन ही देना चाहिए। बच्चों का इम्यून सिस्टम (रोग प्रतिरोधक क्षमता) बड़ों जितना मजबूत नहीं होता। कच्चा दूध पीने से बच्चों को गंभीर उल्टी-दस्त, फूड पॉइजनिंग या किडनी से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं।



शहद और जूस

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, एक साल से कम उम्र के बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें इंफेंट बोटुलिज्म का जोखिम होता है। इसी तरह 12 महीने से कम उम्र में फल या सब्जियों का जूस भी नहीं देनी है, कई बार पैकेट वाले जूस में चीनी और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा भी अधिक हो सकती है जिससे सेहत को खतरा रहता है।



हंसना मना है

रिश्तेदार- बेटा आगे जिंदगी में क्या करोगे... लड़का - कुछ भी करुंगा लेकिन किसी के घर जाकर उनके बच्चों से ऐसे सवाल नहीं करुंगा...

पिता (अपनी बेटी से) - बेटी, पहले तुम मुझे पापा बुलाती थी, अब डैड क्यों कहने लगी हो... बेटी - वो पापा बोलने से मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती है ना...

क्लास में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा- बताओ, कांटों भरे रास्ते पर आपका साथ कौन देगा, पति, पत्नी, भाई, बहन, मां-बाप, प्रेमी, प्रेमिका या दोस्त.. पप्पू खड़े होकर बोला - सर चप्पल... फिर मास्टर जी ने भी चप्पल से की पप्पू की पिटाई...

पति-मुझे अजीब सी बीमारी हुई है, मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता.. हकीम-माशाल्लाह ये बीमारी नहीं, ये तुम पर खुदा की रहमत हुई है..

एक महिला एक साधु के पास गई और बोली-महाराज! आपने प्रवचन में कहा था, अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है। पर जब मैं आईना देखती हूं, तो सोचती हूं मैं कितनी सुंदर हूं तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है, मैं क्या करूं? साधु ने कहा- बेटी यह अहंकार नहीं, गलतफहमी है और गलतफहमी कोई पाप नहीं।

कहानी | घमंड कभी न करना

स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गये थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। स्वामी जी भारत वापस आकर एक दिन घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गये। वहां उन्होंने देखा कि एक नाव किनारा छोड़ चुकी है। तब वे नाव के वापस आने के इंतजार में वहीं किनारे पर बैठ गए। साधु ने स्वामी जी को वहां अकेला बैठा देखा स्वामी जी से पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हुए हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहां नाव का इंतजार कर रहा हूं। साधु ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूं। साधु ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा! तो तुम वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जा कर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ, नदी के पानी के ऊपर चल कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। साधु ने स्वामी जी से कहा, क्या पानी पर पैदल चल कर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है। आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा। बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने बीस सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। यह देख कर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी जिन्दगी के बीस साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए, जो काम एक नाव पांच मिनट में कर सकती है। आप ये बीस साल निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे। या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे। परंतु आपने अपने बीस साल सिर्फ पांच मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। साधु सिर झुकाए खड़े रह गये और स्वामी जी नाव में बैठ कर नदी के दूसरे किनारे पर चले गए।

7 अंतर खोजें





पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष दफ्तर में सहकर्मियों के सहयोग से लंबित कार्य आसानी से निपटेंगे। व्यापार में नए संपर्क बनेंगे, लाभ के योग मजबूत हैं। मित्रों और परिजनों के साथ संवाद से मन हल्का रहेगा।

वृषभ कार्यक्षेत्र में नए दायित्व मिल सकते हैं, दिन व्यस्तता भरा रहेगा। व्यापारिक फैसलों में वरिष्ठों की सलाह लाभदायक सिद्ध हो सकती है। विश्वास बढ़ाने का प्रयास करें।

मिथुन भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए आधिकारिक काम गति पकड़ सकते हैं। लंबी अवधि के निवेश या नई डील पर विचार कर सकते हैं। लेकिन फैसले सोच-समझकर लें।

कर्क लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें, जल्दबाजी से बचें। जीवनसाथी के विचारों का सम्मान करने से रिश्ते मजबूत होंगे। अचानक होने वाले खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

सिंह साझेदारी और टीमवर्क से जुड़े कार्यों में सफलता पाने के अवसर मिल सकते हैं। नए व्यावसायिक अनुबंधों पर बातचीत आगे बढ़ सकती है।

कन्या कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली की सराहना हो सकती है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में धैर्य और रणनीति से काम लें। रिश्तेदारों से बातचीत के दौरान सकारात्मक रवैया रखें।

तुला बौद्धिक कार्यों और लेखन से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। नए विचारों से व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। धन संचय के लिए खर्चों की समीक्षा करें।

वृश्चिक घरेलू चिंताओं को काम पर हावी न होने दें और एकाग्र रहें। अचल संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में सावधानी से निर्णय लें। पारिवारिक मामलों को शांति से सुलझाने का प्रयास करें।

धनु आपका पराक्रम और प्रभाव बढ़ सकता है, निर्णय सोच-समझकर लें। छोटी यात्राओं से व्यापार के नए अवसर मिल सकते हैं। भाई-बहनों के साथ तालमेल बनाए रखें।

मकर वाणी की मधुरता से अधिकारियों और सहयोगियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। फंसा हुआ पैसा वापस पाने के लिए प्रयास तेज कर सकते हैं। खानपान संतुलित रखें।

कुम्भ अपने व्यक्तित्व और कार्यकुशलता से कार्यक्षेत्र में पहचान बनाने का प्रयास करेंगे। नई योजनाओं की शुरुआत से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें।

मीन सहकर्मियों के काम पर जरूरत के अनुसार नजर रखें और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। दूरस्थ स्थानों से जुड़े व्यापार में नए अवसर तलाश सकते हैं।

बॉलीवुड की लॉबी ने किया था करियर तबाह: ओबेरॉय

बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय एक बार फिर अपने पुराने विवाद को लेकर चर्चा में हैं। साल 2003 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय से जुड़े विवाद के बाद अभिनेता की जिंदगी और करियर में काफी उथल-पुथल मची थी। अब वर्षों बाद विवेक ने उस मुश्किल दौर को याद करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। विवेक का कहना है कि उस विवाद के बाद फिल्म इंडस्ट्री की एक ताकतवर लॉबी उनके खिलाफ हो गई थी। हालात ऐसे बन गए थे कि फिल्में सफल होने और अवॉर्ड जीतने के बावजूद उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। यहां तक कि जिन लोगों ने शुरुआत में उनका साथ देने का वादा किया था, उन्होंने भी बाद में उनसे दूरी बना ली। अभिनेता ने बताया कि उस समय उन्हें काफी अकेलापन, गुस्सा और कड़वाहट महसूस होती थी। उनके मुताबिक, उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन इसके बाद उन्हें लगातार परेशान किया जाने लगा। विवेक ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि उनके खिलाफ एक ऐसा माहौल बना दिया गया था, जिसकी वजह से लोग उनके साथ काम करने से डरने लगे थे। विवेक ने उस दौर को याद करते हुए कहा, मेरी जिंदगी का वह बेहद अंधकारमय समय था। मैंने एक चीज के लिए आवाज उठाने की कोशिश की थी। मेरी सोच थी कि कुछ सीमाएं होती हैं, जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और उनके साथ एक खास तरीके से व्यवहार होना चाहिए। मुझे जो गलत लगा, उसके खिलाफ मैं खड़ा हुआ और इसके बाद मुझे काफी परेशान किया जाने लगा। विवेक ने कहा, सफल फिल्में देने, हिट देने और अवॉर्ड जीतने के बावजूद एक बहुत ताकतवर लॉबी हावी हो गई थी। मैं ऐसा इंसान बन गया था, जिसके साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। जिन फिल्मों को मैं साइन कर चुका था, उनसे भी लोग पीछे हटने लगे। वे कहते थे कि माफ करना, अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता।

बोले- सफल फिल्में देने के बावजूद नहीं मिला था काम



पंचायत 5 का इंतजार कर रहे फैंस को झटका

फैंस मोस्ट अवेडेट सीरीज पंचायत के सीजन 5 के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्राइम वीडियो का यह हिट शो वहीं से आगे बढ़ेगा, जहां पिछले सीजन के अंत में गांव के नाटकीय चुनाव के नतीजे आए थे। द वायरल फीवर द्वारा निर्मित और चंदन कुमार द्वारा रचित इस शो के मेकर्स ने आखिरकार सीजन 5 की रिलीज डेट के बारे में जानकारी दी है। पहले मेकर्स ने संकेत दिया था कि पंचायत 5 अक्टूबर या नवंबर 2026 के आसपास दर्शकों को देखने को मिलेंगे। अब पंचायत सीजन 5 की नई रिलीज डेट सामने आई है। ऐसे में उन दर्शकों को झटका लग सकता है, जो इस साल इसे देखने का इंतजार कर रहे थे। प्राइम वीडियो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, पंचायत सीजन 5। इस साल नहीं आएगा। बताते हुए खेद है, पंचायत का अगला सीजन कैद है। अमेजन प्राइम वीडियो की हालिया घोषणा के अनुसार, जहां पहले की रिपोर्ट्स में 2026 के आखिर में इसके रिलीज होने की बात कही गई थी। वहीं अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने भूषण (बनराकस) की तस्वीर वाला एक रहस्यमयी प्रमोशनल पोस्टर शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि नया सीजन डिले हो गया है। यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और दर्शकों की ओर से इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से पंचायत सचिव बने अभिषेक त्रिपाठी, जिनका फुलेरा का सफर सीजन 5 की कहानी का मुख्य हिस्सा है। एक बार फिर जितेंद्र कुमार के रूप में नजर आएंगे।

2026 में नहीं रिलीज होगी सीरीज



सलमान के निशाने पर आये कनिका और लव गिल

बिग बॉस 20 के हालिया वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट्स से सवाल-जवाब किए। लव गिल के अपने दोस्तों के प्रति बर्ताव पर सवाल उठाने से लेकर, साथी कंटेस्टेंट्स से बहस करने पर कनिका मान पर गुस्सा होने तक, सलमान ने पिछले हफ्ते घर के अंदर हुई कई घटनाओं पर बात की। स्काउटओपी को भी मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा। सलमान ने यंग डीएसए के साथ उनकी लड़ाई और बाकी घर वालों के साथ बार-बार होने वाली उनकी बहस को लेकर उनसे सवाल किए। लव गिल को लेकर जो प्रोमो आउट हुआ है, उस पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि, कनिका और लव को सलमान खान के कुछ काफी असहज करने वाले सवालों का सामना करना पड़ा। सलमान ने लव पर स्काउट को प्रभावित करने और सहानुभूति पाने के लिए झगड़ों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, वहीं उन्होंने कनिका को चेतावनी दी कि वह जिससे बात कर रही हैं, उसके हिसाब से अपना बर्ताव न बदलें। यह चर्चा तब और गरमा गई जब कनिका की काजी तौकीर और आम्रपाली दुबे के साथ बहस हो गई। शो के नए प्रोमो में सलमान खान घरवालों से पूछते हैं कि लव गिल की जगह कोई और होता, तो वो कैसे व्यवहार करता। इस पर सबसे पहले आम्रपाली जवाब देती हैं कि वो सीधे पीछे हट जातीं। उदिति भी कहती हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी चीज है और इसे वो खींचती नहीं। अरिश्फा का कहना था कि काशवी के आने के बाद से ही लव को पीछे हट जाना चाहिए था। घरवालों के जवाब के बाद सोशल मीडिया पर लोग भी जमकर इस प्रोमो पर रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि, घर के बाहर लोगों का सोचना अलग ही है। लव को गलत कहने के साथ-साथ स्काउट के कैरेक्टर पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- वो दूध पीता बच्चा है क्या, जो उसे लव कुछ भी कह दे रही है। एक ने लिखा- गलती हमेशा लड़की की ही होती है, तभी उन्हें सतर्क रहना चाहिए।



जुहू चौपाटी पर छठ पर्व में शामिल हुईं तमन्ना भाटिया

चार दिवसीय छठ पर्व आज सोमवार को संपन्न हो गया है। मूल रूप से इसे बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में मनाया जाता है। दिल्ली, मुंबई से लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में भी लोक-आस्था का यह त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। कल रविवार को मुंबई के जुहू चौपाटी में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया भी छठ पूजा में शामिल हुईं। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया मुंबई में आयोजित छठ पूजा उत्सव में शिरकत करने पहुंचीं। उन्होंने छठी मइया से अपने जुड़ाव का जिक्र किया और साथ ही फिल्म द वन में इस त्योहार को करीब से समझने के बारे में बताया। बता दें कि फिल्म द वन में छठ पूजा को दिखाया गया है। एक गाने में तमन्ना भाटिया यह महापर्व मनाती नजर आई हैं। तमन्ना भाटिया ने मुंबई में छठ पूजा में शामिल होकर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया है और लिखा है, देवी का आशीर्वाद और आप सबका प्यार, छठी मइया की कृपा बनी रहे। जय छठी मइया। तमन्ना ने कहा कि छठी मइया के साथ उन्हें जो जुड़ाव महसूस हुआ है, उसे वे शब्दों में बयान नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा तमन्ना ने बताया कि वे बिहार जाकर इस त्योहार को देखना चाहती थीं। तमन्ना ने कहा, मैं अपने शहर मुंबई में इतने सारे लोगों के साथ छठ पूजा मनाकर बहुत खुश हूं। मुझे बहुत प्यार मिला है। इस महापर्व का महत्व हमेशा मेरे साथ रहेगा। आगे कहा, जब मैं प्रमोशन के दौरान पटना गई और गंगा आरती में शामिल हुई, तो मैं कम से कम एक बार वहां छठ पूजा देखने के लिए वापस जाना चाहती थी। मुझे लगा कि मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन फिर मुझे यहां (मुंबई में) बुलाया गया। मैं बेहद खुश हूं। तमन्ना ने बताया कि वन फिल्म के गाने की शूटिंग शुरू करने से पहले उन्होंने इस रस्म का महत्व और बिहार और पटना में इसे कैसे किया जाता है, यह समझने और पढ़ने में समय बिताया। एक्ट्रेस ने कहा, सच कहूं तो, इसकी शक्ति के बारे में जानकर मैं हैरान रह गई। छठी मइया के साथ मेरा जो गहरा जुड़ाव महसूस हुआ, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मैंने खुद को उनसे बहुत जुड़ा हुआ महसूस किया।

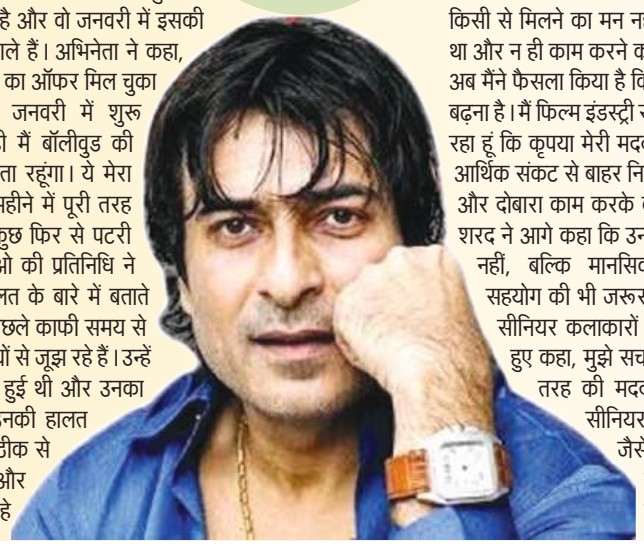
बोली- बिहार जाकर देखना चाहती थीं छठ पूजा



शरद कपूर ने बॉलीवुड में मांगा था काम, हॉलीवुड का मिला ऑफर

फिल्म जोश में अपनी दमदार भूमिका से पहचान बनाने वाले अभिनेता शरद कपूर इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह अपनी तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण अपने पालतू डॉग्स को एक एनजीओ की देखरेख में भेजते नजर आए थे। इसके बाद एनजीओ प्रतिनिधि ने वीडियो पोस्ट किया। उसमें शरद ने खुलकर बताया कि वह डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और पिछले दो साल से बिस्तर पर हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा है कि उन्हें काम और आर्थिक मदद की जरूरत है, ताकि वह दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसी बीच अभिनेता ने बताया कि उन्हें एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर मिला है। शरद कपूर ने बताया कि उन्हें एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर मिला है और वो जनवरी में इसकी शूटिंग भी शुरू करने वाले हैं। अभिनेता ने कहा, मुझे एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर मिल चुका है, जिसकी शूटिंग मैं जनवरी में शुरू करूंगा। इसके साथ ही मैं बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम करता रहूंगा। ये मेरा देश है। जैसे ही मैं दो महीने में पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, सब कुछ फिर से पटरी पर आ जाएगा। एनजीओ की प्रतिनिधि ने वीडियो में शरद की हालत के बारे में बताते हुए कहा कि अभिनेता पिछले काफी समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्हें दिमाग से जुड़ी समस्या हुई थी और उनका पैर भी टूट गया था। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह ठीक से कुछ खा भी नहीं रहे थे और न ही अपनी दवाइयां ले रहे थे। यहां तक कि उन्हें ठीक से बोलने में भी परेशानी हो रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि शरद करीब दो साल से बिस्तर पर थे। शरद ने अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बात करते हुए बताया कि कुछ परिस्थितियों और लोगों के आरोपों ने उन्हें काफी दुख पहुंचाया। उन्होंने कहा, जब कोई बिना किसी वजह के आप पर आरोप लगाता है, तो दुख होता ही है। मैं डिप्रेशन में चला गया था। मेरा किसी से मिलने का मन नहीं करता था और न ही काम करने का। लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मुझे आगे बढ़ना है। मैं फिल्म इंडस्ट्री से अपील कर रहा हूं कि कृपया मेरी मदद करें। मैं इस आर्थिक संकट से बाहर निकलना चाहता हूं और दोबारा काम करके कमाना चाहता हूं। शरद ने आगे कहा कि उन्हें सिर्फ पैसों की ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहयोग की भी जरूरत है। उन्होंने इंडस्ट्री के सीनियर कलाकारों से मदद की अपील करते हुए कहा, मुझे सच में आर्थिक और नैतिक दोनों तरह की मदद चाहिए। इंडस्ट्री के मेरे सभी सीनियर कलाकारों, आप सभी मेरे लिए बॉस जैसे हैं। मैं आप सभी का बहुत बड़ा फैन हूं और हमेशा आपको अपना हीरो मानता आया हूँ।

अभिनेता ने बताया जनवरी से शुरू करुंगा शूटिंग



राजस्थान व हरियाणा की भाजपा सरकारों पर कांग्रेस का प्रहार

भजन सरकार ने बना दिये राज्य में अकाल जैसे हालात : अशोक गहलोत

» कांग्रेस नेता बोले- सरकार किसका इंतजार कर रही है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भाजपा की राज्य सरकारों पर प्रहार किया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान को पूरा पानी नहीं मिलने और पचपदरा रिफाइनरी के पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल उद्योग शुरू नहीं होने के मुद्दे पर भजनलाल सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब की ओर से राजस्थान को मिलने वाले पानी की आपूर्ति कम की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। वहीं हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान हर साल महंगाई बेतहाशा गति से बढ़ती जा रही है। आज पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। खेती के उपकरणों से लेकर खाद, बीज, दवाई और मजदूर तक इतनी महंगी हो गई है कि किसान खेती छोड़ने को मजबूर हैं।

गहलोत ने सरकार से पंजाब और केंद्र के साथ बातचीत कर राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी लेने की मांग की है। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पंजाब सरकार कभी किसान आंदोलन तो कभी नहरों की मरम्मत का हवाला देकर राजस्थान को पानी की आपूर्ति घटा देती है। कई बार राजस्थान सरकार को इसकी जानकारी दिए बिना ही पानी कम कर दिया जाता है। ऐसे हालात में प्रदेश सरकार मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती। गहलोत ने पश्चिमी राजस्थान में पेयजल संकट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अकाल जैसे हालात हैं। ऐसे समय में पश्चिमी राजस्थान के लिए पानी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बावजूद जोधपुर के लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले ढाई साल से जोधपुर को रोजाना करीब ढाई एमसीएफटी पानी कम मिल रहा है। इसका असर कायलाना और तखतसागर झीलों के जलस्तर पर भी पड़ा है। जलस्तर नहीं बढ़ने से जोधपुर शहर और आसपास के गांवों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। गहलोत ने राज्य सरकार से सवाल किया कि जब जोधपुर के लोग पानी के लिए परेशान हैं तो सरकार आखिर किसका इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिलना किसी सरकार की मेहरबानी नहीं, बल्कि प्रदेश का अधिकार है।





रिफाइनरी का कच्चा माल दूसरे राज्यों में जाने पर उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री ने बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी के साथ विकसित किए जा रहे पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल उद्योग स्थापित नहीं होने पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जमीन पर रिफाइनरी स्थापित हुई, लेकिन पेट्रोकेमिकल उद्योग नहीं लगने से प्रदेश को मिलने वाले रोजगार और औद्योगिक विकास के अवसर दूसरे राज्यों में जा सकते हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि रिफाइनरी से निकलने वाले कच्चे माल के प्रसंस्करण के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता की स्थिति बन रही है। इससे उद्योगों का लाभ और रोजगार भी दूसरे राज्यों को मिलेगा, जबकि राजस्थान के युवाओं को इसका अपेक्षित फायदा नहीं मिल पाएगा। गहलोत ने कहा कि पचपदरा में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय उनकी सरकार ने तत्कालीन यूपीए सरकार के सहयोग से लिया था। इसके लिए पेट्रो जोन में भूमि भी आवंटित कर दी गई थी।

किसानों के साथ भद्दा मजाक कर रही सैनी सरकार : हुड्डा

कांग्रेस के वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान को पूरे हरियाणा में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह बीजेपी की वोट चोरी पकड़ी गई है, उसके चलते जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। 2029 के चुनाव में जनता भाजपा व चुनाव आयोग को वोट चोरी नहीं करने देगी। रोहतक में हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा गन्ने के रेट में मात्र 15 रुपये की बढ़ोत्तरी करना, किसानों के साथ भद्दा मजाक है। गन्ने की कीमत में सरकार ने मात्र 3 प्रतिशत वृद्धि की है। जबकि महंगाई आसमान छू रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस सरकार के साढ़े 9 साल (2005 से 2014) में गन्ने के रेट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई। उस समय गन्ने का रेट 117 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 310 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया था। यानी कुल रुपये 193 की बढ़ोतरी हुई यानी 165 प्रतिशत। इस दौरान औसतन हर साल करीब 18.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वहीं, भाजपा सरकार के 12 साल में गन्ने के रेट में सिर्फ रुपये 120 की बढ़ोतरी हुई। इसे रुपये 310 से बढ़ाकर रुपये 430 प्रति क्विंटल किया गया, जो कुल मात्र 39 प्रतिशत की वृद्धि है। इस अवधि में औसतन हर साल सिर्फ करीब 3.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यानी कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले 6 गुणा ज्यादा बढ़ोत्तरी की। अन्य फसलों की भी बात की जाए तो कांग्रेस कार्यकाल में फसलों के रेट में हर साल औसतन 14-15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होती थी। जबकि बीजेपी के कार्यकाल में यह घटकर मात्र 5 प्रतिशत रह गई है। यानी कांग्रेस एमएसपी में बीजेपी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बढ़ोत्तरी करती थी।

जय शाह को दूसरी बार मिली आईसीसी की कमान

» बीसीसीआई, सचिन, गंभीर और मिथुन मन्हास ने दी बधाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को लगातार दूसरी बार इस पद की जिम्मेदारी मिलने पर भारतीय क्रिकेट जगत में खुशी की लहर है। बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मन्हास, टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर और पूर्व क्रिकेटरों समेत कई दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी है। जय शाह को सोमवार को इंडोनेशिया के बाली में हुई आईसीसी बोर्ड की बैठकों के दौरान दूसरी बार निर्विरोध आईसीसी चेयरमैन चुना गया। उनका नया कार्यकाल दिसंबर 2027 से शुरू होकर दिसंबर 2030 तक चलेगा। इससे पहले अगस्त 2024 में वह पहली बार इस पद के लिए चुने गए थे। उस समय 35 वर्ष की उम्र में वह आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन बने थे।

बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने जय शाह को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टिकोण और क्रिकेट के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि जय शाह के प्रयासों ने क्रिकेट की वैश्विक पहचान और लोकप्रियता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। गंभीर ने एक्स पर लिखा, एक और योग्य कार्यकाल के लिए बधाई जय शाह भाई। आपके नेतृत्व पर भरोसा खुद सब कुछ बयां करता है। तेंदुलकर ने कहा कि क्रिकेट के विकास के लिए नए अवसर पैदा करना, खेल के इकोसिस्टम को मजबूत करना और इसे नए दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। जय शाह का दूसरा कार्यकाल ऐसे समय शुरू होगा, जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सामने कई बड़ी चुनौतियां और अवसर होंगे। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में 2027 वनडे विश्व कप का आयोजन होना है। इसके बाद लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट की वापसी होगी। आईसीसी की प्राथमिकताओं में क्रिकेट का वैश्विक विस्तार, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ढांचे को मजबूत करना, खेल में भागीदारी बढ़ाना और महिला क्रिकेट को नए अवसर देना शामिल है।



मिताली राज और यास्तिका भाटिया ने महिला क्रिकेट के विकास को सराहा

पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज और महिला क्रिकेटर यास्तिका भाटिया ने भी जय शाह को दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। मिताली ने कहा कि महिला क्रिकेट के विकास के लिए सार्थक अवसर तैयार करने और खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में जय शाह का विजन और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण रही है। यास्तिका ने उनके निर्विरोध दोबारा चुने जाने को नेतृत्व और दूरदर्शिता की पहचान बताया। इसके अलावा शिखर धवन, केएल राहुल समेत कई अन्य क्रिकेटरों ने भी जय शाह को शुभकामनाएं दीं।

न्यूजीलैंड को झटका: मिचेल सैंटनर टेस्ट सीरीज से बाहर

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के अनुभवी स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर और सीमित ओवरों के कप्तान मिचेल सैंटनर चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। पांचवें और आखिरी वनडे मुकाबले के दौरान उनके दाएं हाथ में चोट लगी थी। जांच में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। सैंटनर न्यूजीलैंड के अनुभवी स्पिन गेंदबाजों में शामिल हैं। वह गेंदबाजी के साथ निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं। ऐसे में उनका बाहर होना न्यूजीलैंड के लिए बड़ा नुकसान है। सैंटनर की जगह सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। फॉक्सक्रॉफ्ट टॉम लैथम की अगुआई वाली टीम का हिस्सा होंगे। उन्होंने मई में आयरलैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था।



हर बार मौतों का इंतजार करता है केडीए!

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कानपुर। शहर में अवैध निर्माणों की बुनियाद पर खड़ी होती बहुमंजिला इमारतें अब लोगों के सपनों का आशियाना नहीं, बल्कि मौत का इंतजार करती इमारतें बनती जा रही हैं। हादसा होता है, जानें जाती हैं, परिवार उजड़ते हैं और उसके बाद प्रशासनिक अमला जागता है। कुछ दिन जांच, नोटिस, सीलिंग और कार्रवाई के दावे होते हैं, लेकिन फिर वही कहानी, वही लापरवाही और वही सवाल! आखिर कानपुर विकास प्राधिकरण का प्रवर्तन दस्ता अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगा? क्या केडीए को हर बार किसी बड़े हादसे और दो-चार मौतों का इंतजार रहता है?

फीलखाना थाना क्षेत्र के पटकापुर स्थित राधिका अपार्टमेंट में सोमवार तड़के लगी भीषण आग ने एक बार फिर इस व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी। ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग से शुरू हुई आग देखते ही देखते सीढ़ियों, रेलिंग और लिफ्ट के रास्ते ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। धुएं ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। बाहर निकलने के पर्याप्त रास्ते और आपातकालीन सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के कारण लोग अपने-अपने फ्लैटों में फंसकर रह गए।

दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन 45 वर्षीय राखी साहू और महज 15 वर्षीय किशोर प्रांजल बाथम को बचाया नहीं जा सका। दो जिंदगियां खत्म हो गईं और करीब 12 परिवारों के आशियाने उजड़ गए। विडंबना देखिए कि जिस इमारत में लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर फ्लैट खरीदे, वही इमारत उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन गई। शहर में 2BHK फ्लैट की कीमत 40 से 45 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सस्ते फ्लैट और बेहतर सुविधाओं का सपना दिखाकर संकरी गलियों में बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा रही हैं। आरोप है कि कहीं गलत नक्शा दिखाकर तो कहीं सुरक्षा इंतजामों का भरोसा देकर लोगों को फ्लैट बेचे जाते हैं। खरीदार को घर की चाबी तो मिल जाती है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि जिस छत के नीचे वह परिवार के साथ रह रहा है, वहां से आपात स्थिति में बाहर निकलने का रास्ता भी सुरक्षित है या नहीं।



घटना के बाद छठ पर्व की छुट्टी में अचानक जागा केडीए, चार निर्माण सील

पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल केडीए की कार्यशैली को लेकर है। जिस दिन छठ पर्व की छुट्टी थी, उसी दिन राधिका अपार्टमेंट में अग्निकांड हुआ और दो लोगों की मौत हो गई। इसके बाद आनन-फानन में केडीए का प्रवर्तन दस्ता सक्रिय हुआ और देर शाम चार निर्माणों को सील कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर इन निर्माणों पर कार्रवाई के लिए हादसे का इंतजार क्यों किया गया? आम दिनों में जब शहर की संकरी गलियों में धड़ल्ले से बहुमंजिला इमारतें तैयार होती हैं, तब प्रवर्तन दस्ता कहां रहता है? छुट्टी के दिन अचानक कार्रवाई की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दो जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं? यदि इन निर्माणों में अनियमितताएं थीं तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या केडीए की निगरानी व्यवस्था सिर्फ हादसों के बाद सक्रिय होती है?

4पीएम ने पहले ही चेताया था फिर क्यों नहीं चेते अधिकारी?

4 PM ने 22 अक्टूबर को योगी सरकार की छवि पर दाग लगा रहे अधिकारी शीर्षक से खबर प्रकाशित कर शहर में अवैध निर्माणों की भरमार और केडीए के प्रवर्तन दस्ते की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। इसके बाद 28 और 30 अक्टूबर को भी प्राधिकरण की कथित अनियमितताओं और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर खबरें प्रकाशित की गईं। संकरी गलियों में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण, स्वीकृत नक्शे और सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसे मुद्दे लगातार उठाए गए। बावजूद इसके क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते कोई प्रभावी कदम उठाया? यदि खबरों पर संज्ञान लिया गया था तो कार्रवाई कहां हुई?

5 फुट की सड़क छह मंजिल की इमारत..



राधिका अपार्टमेंट के मामले में प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक करीब चार मीटर चौड़ी सड़क पर पांच से छह मंजिला इमारत खड़ी है। ग्राउंड फ्लोर पर स्पार्किंग से आग लगने की बात सामने आई है। इसके बाद आग सीढ़ियों के रास्ते ऊपर तक पहुंच गई। जांच में पर्याप्त आपातकालीन निकास की व्यवस्था तक नहीं थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी संकरी सड़क पर इतनी ऊंची इमारत का निर्माण किन मानकों के तहत हुआ? क्या भवन का नक्शा स्वीकृत था? क्या वास्तविक निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप है? क्या अग्निशमन विभाग से जरूरी अनापत्ति और सुरक्षा संबंधी इंतजाम पूरे किए गए थे? क्या भवन में फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास, सुरक्षित सीढ़ियां और आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम थे? यदि नहीं, तो निर्माण के दौरान संबंधित विभागों ने क्या किया? क्या केडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कभी इस भवन का निरीक्षण किया? यदि निरीक्षण हुआ तो खामियां क्यों नहीं पकड़ी गईं? और यदि जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी हादसे के बाद नोटिस जारी करने या इमारत सील करने से पूरी नहीं होती। असली जिम्मेदारी तब होती है, जब निर्माण की पहली ईंट रखी जाती है और नियमों को ताक पर रखकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जाती हैं।

हादसों की फेहरिस्त लंबी, लेकिन सबक लेने को कोई तैयार नहीं!

कानपुर में आग और असुरक्षित निर्माण से जुड़े हादसों का इतिहास भी कम डरावना नहीं है। **4PM** की प्रकाशित खबरों में सामने आए घटनाक्रम पर नजर डालें तो तस्वीर और भयावह हो जाती है। **16 सितंबर 2022 :** फजलगंज में सार्वजनिक पार्किंग बनाने वाले फैक्ट्री परिसर में आग लगने से तीन मजदूरों की मौत हो गई थी। **31 मार्च 2023:** बांसमंडी के हमराज़ कॉम्प्लेक्स के टावरों में लगी भीषण आग में एक मजदूर की मौत हुई, जबकि 200 से ज्यादा दुकानें राख हो गई थीं और अरबों-करोड़ों का नुकसान हुआ था 3 दिन बाद आग बुझी थी।
14 मई 2025: कलक्टरगंज के गलामंडी क्षेत्र में आग से 75 दुकानें जल गईं और दो मजदूरों की जान चली गई।
5 मई 2025: चमनगंज के प्रेमनगर में बहुमंजिला भवन में नीचे कारखाना चलता था आग लग गई थी आग से कारोबारी मो. दानिश, पत्नी नाजली सबा और तीन बेटियों सारा, सिमरा व दानिया की मौत हो गई थी।

नहीं उठा केडीए वीसी और सचिव का फोन

संबंधित प्रकरण में कानपुर विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों से उनका पक्ष जानने के लिए 4PM संवाददाता प्रांजुल मिश्रा ने फोन करके पक्ष जानने का प्रयास किया लेकिन ख़बर लिखे जाने तक सचिव और केडीए VC से बात नहीं हो सकी। राधिका अपार्टमेंट में लगी आग के प्रत्यक्षदर्शियों और सामने रह रहे लोगों ने बताया की अपार्टमेंट 1-2 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है लेकिन प्राधिकरण के जिम्मेदार अपने बचाव के लिए कह रहे हैं अपार्टमेंट का निर्माण 5 साल पहले हुआ था जो लोग यहां से नौकरी करके जा चुके हैं या रिटायर हो गए हैं तो उनके खिलाफ करवाई क्या होगी...? मौजूदा जिम्मेदार अभी भी नौकरी कर रहे हैं यह दर्शाने का प्रयास हो रहा है कि अपार्टमेंट 5 साल पहले बनकर तैयार हुआ था जब मौजूद जिम्मेदार कानपुर विकास प्राधिकरण की सेवा में नहीं थे मतलब साफ है खुद को सेफ़ जोन करने का प्रयास हो रहा है...?

बिल्डर ही नहीं, जिम्मेदार अधिकारी भी जांच के दायरे में आएं

राधिका अपार्टमेंट के निर्माण और बिक्री से जुड़े बिल्डर मोहित तिवारी और प्यारे की भूमिका भी जांच का विषय है। क्या नक्शा स्वीकृत था? क्या निर्माण उसी के अनुरूप हुआ? क्या फ्लैट खरीदारों को सुरक्षा इंतजामों की सही जानकारी दी गई? अपार्टमेंट के आसपास बन रही अन्य बहुमंजिला इमारतों की भी जांच जरूरी है। अग्निकांड के बाद पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल और जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घायलों के उपचार की जानकारी ली और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने केडीए उपाध्यक्ष से वार्ता कर अनधिकृत और असुरक्षित इमारतों को चिह्नित करने तथा संयुक्त अभियान चलाने की बात भी कही। लेकिन सवाल है कि आनन फानन क्या चार निर्माणों की सीलिंग के बाद अभियान थम जाएगा या पूरे शहर में ऐसी इमारतों की जांच होगी? क्या स्वीकृत नक्शों और वास्तविक निर्माण का मिलान होगा? क्या उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी जिनकी निगरानी में ये इमारतें खड़ी हुईं? आपके अपने जिम्मेदार अख़बार 4 PM ने हादसे से पहले सवाल उठाए थे, लेकिन अब दो मौतों के बाद केडीए की सक्रियता कई नए सवाल खड़े कर रही है। आखिर आम दिनों में कार्रवाई क्यों नहीं होती? छुट्टी के दिन ही प्रवर्तन दस्ते को इतनी तेजी क्यों दिखानी पड़ी? क्या कानपुर में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के लिए अब किसी और हादसे का इंतजार किया जाएगा? राधिका अपार्टमेंट की आग सिर्फ दो जिंदगियां नहीं ले गई, बल्कि केडीए की निगरानी व्यवस्था को भी कठघरे में खड़ा कर गई। अब जरूरत आनन-फानन की कार्रवाई की नहीं, बल्कि नियमित निगरानी, निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की है।

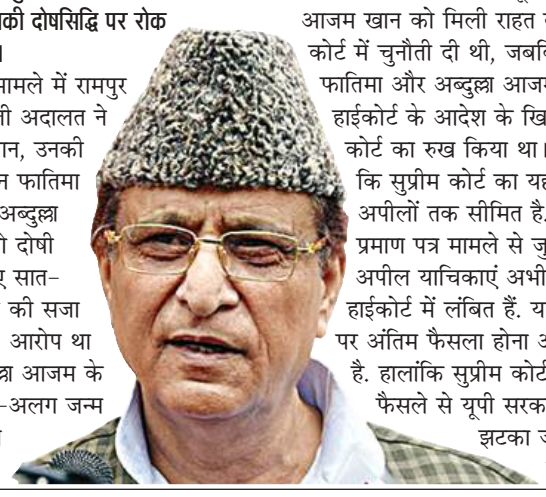
यूपी सरकार को झटका, याचिका खारिज

आजम खां और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत को बरकरार रखा है और उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत देते हुए उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है।

इस मामले में रामपुर की निचली अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी. आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए थे. एक प्रमाण पत्र में उनका जन्म रामपुर और दूसरे में लखनऊ में होना बताया गया था. आरोपों के मुताबिक, इन दस्तावेजों का इस्तेमाल चुनावी लाभ लेने के लिए किया गया था। मई 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी और बेटे को दोषसिद्धि पर रोक लगाने से राहत देने से इनकार कर दिया था. यूपी सरकार ने आजम खान को मिली राहत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जबकि तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इन अपीलों तक सीमित है. फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले से जुड़ी मुख्य अपील याचिकाएं अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं. यानी मामले पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी सरकार को झटका जरूर लगा है।



टिहरी गढ़वाल के गुलार बाजार के पास गहरी खाई में गिरी बस

» 8 लोगों की दर्दनाक मौत और 20 से अधिक घायल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

देहरादून। उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार सुबह (17 नवंबर 2026) टिहरी गढ़वाल जिले के गुलार बाजार के पास एक बड़ा और दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।

मंगलवार सुबह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में गुलार बाजार के पास एक बस पुल से लगभग 100 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई, जिससे कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। टिहरी जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, दुर्घटना की सूचना मिलते ही ब्यासी और ढालवाला स्थित स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (स्ष्ठक्रस्र) की टीमों को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया। टिहरी की जिला मजिस्ट्रेट नितिका खंडेलवाल और स्स्क्र श्वेता चौबे भी घटनास्थल के लिए निकल गई हैं। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, बस में लगभग 30-35 लोग सवार थे, जिनमें से करीब 20 घायलों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और बचाव अभियान अभी भी जारी है।



महाराष्ट्र कार्यालय:- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क, 2-डी सिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400053। **विधि सलाहकार**: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website**: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी **4** पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक **संजय शर्मा**
द्वारा **आस्था प्रिंटर्स**, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। **संपादक- संजय शर्मा**